

[Shri S. R. Damani]

suggested four-laning of this road even in the Fourth Plan period at a cost of Rs. 17.5 crores. The portion between Khopoli and Lonawala is particularly hazardous, zig-zag and steep-graded and a large number of accidents and breakdowns are daily occurrences; and hundreds of passengers are killed monthly. The Government of India approved the realignment of this portion as far back as March 1973. But implementation was not forthcoming. As a first step, the State Government proposed, to the Government of India to construct a two-lane carriage way that an estimated cost of just Rs. 3 crores. Considering the very heavy traffic on this National Highway, I suggest that (a) the work is of four-laning the road between Panvel and Dahu Road; (b) realignment with a two-lane carriage way between Khopoli and Lonawala and (c) the construction of westerly diversion outside Pune City, can brook no further delay and the Government of India should take immediate action to implement these works.

श्री किरणो प्रसाद (बांसगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: अवस्था क्या है ?

श्री किरणो प्रसाद: घाग मुन नीजिये। अभी कुछ चन्द मिनट पहले श्री राम प्रवर्धन सिंह ने काका कानेलकर की रिपोर्ट पर बहस के लिए कहा था। मैंने भी उस पर लिख कर दिया है। जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि काका कानेलकर की रिपोर्ट को लागू करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, किसी समय किसी ने कुछ कह दिया और आप हम तरह से उस के लिये खड़े हो जायेंगे, यह ठीक नहीं है।

Now Mr Raj Narain.

(iii) REPORTED SELECTION OF AIRCRAFT FOR INDIAN AIR FORCE.

श्री राज नारायण (राय बरेली): श्रीमन्, सदन को तो ज्ञान ही है कि हमारी वायु सेना को अपने कुछ पुराने विमानों के बदले नये जहाज खरीदने की सख्त जरूरत है। इसके लिये सरकार ने कई कमेंटीयों भी बनाई थीं। पिछले सेशन में हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री श्याम नन्दन मिश्र ने मबाल उठाया था कि विदेशी पत्रिकाओं में हल्ला है कि विमान को हम चुन चुके हैं, तथा उसके लिए कुछ कमीशन भी बांटे गये हैं। हम यह समझते थे कि सीधा तय करने के पहले इस विषय पर सदन में प्रकाश डाला जायेगा।

यह पुरानी खबर सायद ठीक नहीं थी, पर दस दिन पहले बम्बई के एक साप्ताहिक समाचार पत्र ने बताया कि फ्रांस के एक अच्छे प्रस्ताव को ठुकराया

गया है। फ्रांस के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को पेरिस जाने का निमन्त्रण भी दिया था। विश्वस्त सुर्खों से हमें यह भी शत हुआ है कि फ्रांस की विमान बनाने वाली कंपनी, एओ की ० मा०, के अध्यक्ष ने अपने नये प्रस्ताव में कहा है कि उन के मिराज एफ-१ को यदि हम खरीदें, तो साथ ही साथ उन के सबसे नये विमान मिराज 2000 को भी ले सकेंगे और वहाँ बना सकेंगे। इस प्रस्ताव को अपनी मान्यता देते हुए उनकी सरकार ने भी लिखा था, पर इसका जबाब हम ने देर से और बिना आवश्यकता दिखाते हुए लिखा—इसका जबाब देर से दिया।

साथ ही साथ विदेशी पत्रिकाओं में पता चला कि अमेरिका चाह रहा है कि हमें विंगेन हवाई जहाज स्वीडन से नमिलें। मुन्ने में धाता है कि सरकारी कमेटी ब्रिटेन के जागृधार विमान खरीदवाना चाहती है, जो कि चार पांच साल के अन्दर यूरोप की वायु सेनाओं की सविन से हट जायेगा, यानी वह पुराने टाइम का है।

यह भी एक विज्ञानजनक बात है कि फ्रांस के मिराज तथा स्वीडन के विंगेन के श्रेष्ठ होते हुए भी जागृधार विमान को ही लेने का निश्चय किया जा रहा है। खबर यह भी है कि हम में भारी कमीशन बंटने की संभावना है। गैमा क्यों हो रहा है, सन को हमकी जान-सारा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यह बात सारे देश के लिये बहुत ही गंभीर और विज्ञान-जनक है। पहली बात तो यह है कि देश के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वायु सेना के बीच सान पुराने विमानों के बदले नये तरह के विमान हम खरीदें, जो कि हमारी जरूरतों को करीब करीब बीस साल तक पूरा करते रहें पर इस के लिए हम हमें विमान के लिए नहीं रुक सकते, जो कि अभी डिजाइन हो किया जा रहा है, क्योंकि हमारे घास-घास के देश बहुत ही शक्तिशाली और नये तरह के विमान तथा मिसाइल खरीद रहे हैं, जिस से हम पर घागे बार हो सकता है। इसलिये हमें जो धन ही नये तरह के विमान की भी आवश्यकता है। ये ऐसे होने चाहिए कि उनके नये माडेल को भी हम बाद में घासानी से खरीद सकें तथा भारत में भी बना सकें।

दूसरी बात यह है कि एक तरह से तो सुपर पावर का दबाव पड़ रहा है कि नये तरह के विमान हमें न मिलें और दूसरी ओर सरकार के भीतर का एक "प्रैतर ग्रुप" या "काकम" चाह रहा है कि एक पुराने विमान को हम खरीदें। गैमा क्यों हो रहा है, इसका कारण जानना आवश्यक है। सरकार से घागह है कि उन कारणों से सदन को प्रभावित करायें।

श्रीमन्, मुझे कहने का मौका दिया जाये कि यह देश तथा यह सदन इस क्षेत्र को चुन-चान न देखेंगे, जिस में हमारे देश तथा इस की वायुसेना को एक पुराने बंगला विमान दिया जा रहा है, जिस पर पम्बक का 1500 करोड़ रुपये का खर्च है, जब कि और भी अच्छे विमान हमें मिल सकते हैं। सरकार इस बात पर अपनी सज्जाई दे। हम ऐसा सम-झौता भी न मानेंगे, जिसमें हमें किसी भी प्रकार

बाल किया जाने कि हम बच्चे परीक्षित, नये विद्यार्थी की बगल पुराने विमान करीब, तथा बेचने वाली का बाबा मार्ग में कि जाने बस कर उन के नये विमान को हम करीब, की कि जमी साबित की न किया गया हो। हमारा क्या विमान ऐसा होना चाहिए कि वह बुरा हो और बित की बुद्धि साबित हो चुकी हों। इस बात पर हम अधिक में देश की हानि देखने को तैयार नहीं हैं।

की स्वातन्त्र्य विषय (सेनेटरिय) : मैं एक बात की सफाई देवें। सामान्य सत्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने पिछले मार्च में यह कहा था कि कमीशन बांटी गई। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि कमीशन बांटने की परियोजना है और अगर कमीशन बांटी जाती है तो कमीशन राज्य को आए, किसी व्यक्ति के हाथ न लगे।

(iv) PUBLIC SCHOOL SYSTEM)

SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan) : Sir, under rule 377, I mention the following matter of urgent public importance.

The coaching system in private schools is creating a gap within the society and day by day the gap is widening between the common men and the affluent. As has been seen, every person of privileged class is anxious to get his kid admitted in a private school by paying huge sums which are demanded in the guise of donations. While our leaders make loud promises for Indianisation, they are absolutely keeping their eyes and ears closed as to how the brains of innocent children are being washed. Instead of making them proud of their heritage, they are made to feel that their culture and way of living in Europe. The typical system adopted by these private schools imparts a perverted culture and makes middle-class sahibs intellectually subservient to half-digested ideas of the middle-class west. Therefore, it is very necessary to go into the details of the functioning of such schools and to determine precisely what kind of a person is created by such institutions. This is a subject which has aroused many suspicions in the minds of the public in general about the way these schools are in operation within the country. They demand higher fees and expect the boys to be better dressed and the medium in all subjects in English. Thereby they create communities of the affluent elites. By destroying their own roots of origin, the boys are alienated from their own people and remain so far the rest of their life.

It is precisely to avoid the turning out of alienated and rootless young men

that 'parents in developed countries have shunned the ideas of public schools system. Yet in India where we hood consciously to promote integration, the State continues to tolerate and ~~maintain~~ special schools, which turn out potential brown sabhes. It has gone so far as to maintain such schools by direct funding and patronising such a system. It is the time that we should seriously think of discarding such a system which is cutting at the very root of integration and making our children subverters of their own culture and heritage. Although the Centre has not been able to feel the pulse and has realised the extent of damage which such private schools are doing to the nation. Perhaps primarily this is the reason that they have already adopted a unanimous resolution in Delhi Metropolitan Council where they have suggested doing away with the Public School Education System to bring uniformity in the standard of education and have recommended that such schools should be brought at par with those of the Government of Government-aided schools.

It is strongly felt that the Centre should move fast in scrapping out the system of public school education so as to bring an end to corrupt practices by the management of these public institutions throughout India.

(v) REPORTED DEATHS AND HEAVY LOSSES DUE TO RAIN IN HIMACHAL PRADESH.

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : I am thankful to the Chair for having permitted me to raise this matter of urgent public importance under rule 377....

This year, Himachal Pradesh has faced heavy and incessant rains causing death of 141 persons. Hundreds of cattle have perished, thousands of houses have collapsed, standing crops have been destroyed and there is heavy erosion of fertile lands, damage to roads, culverts and bridges by landslides, particularly in Kangra, Chamba, Mandi, Bilaspur, Hamirpur and Solan District. The total loss as per reports amounts to several crores of rupees. This is too much for a backward State to bear such a heavy loss on account of natural calamities.

There is an urgent need to provide adequate funds from the Central Exchequer for relief measures in the worst affected regions in the State and to send a Central Study Team to make an on the spot assessment of the havoc wrought by the heavy rains in this State and the damage caused by the earthquake shocks in the Dharma-sala area (District Kangra).